आवारा कुत्तों से परेशान लोग : आखिर क्या करें?

फ़रीदाबाद (म.मो.) शहर के लोग़ आवारा कुत्तों से बुरी तरह परेशान हैं। एक दिन भी नहीं बीतता कि जब आवारा कुत्ते किसी न किसी बच्चे को न काट खाते हैं। डॉक्टरों के यहां ऐसे मरीज़ों की लाइन लगी रहती है जिन्हें कुत्तों ने काट खाया हो। कुत्ते का काट लेना एक जानलेवा बीमारी है, अगर तुरंत इसका इलाज शुरू नहीं किया गया। पहले सरकारी अस्पतालों में कुत्ता काटने का मुफ़्त में इलाज़ होता था। रैबीज के टीके अस्पताल में उपलब्ध रहते थे। इन टीकों को बनाने के लिए चंद भेड़ों की बलि ली जाती थी। इससे मेनका गांधी जैसे पशुप्रेमियों को काफ़ी वेदना हुई और उन्होंने सदल-बल इतना शोर-शराबा मचाया कि इस दवा का उत्पादन ही बंद कर दिया गया। अब कुत्ता काटने का कोई मरीज़ सरकारी अस्पतालों में पहुंचता है तो वे यह कह कर कि उनके पास टीके नहीं हैं, अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। परिणामस्वरूप, कुत्ता काटे मरीज़ का निजी क्लिनिकों में जाना पड़ता है और हज़ारों रुपये खर्च कर टीके लेने पड़ते हैं। अगर टीके लेने में देर हो गई तो हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी हो जाती है और यह हो जाने पर किसी भी डॉक्टर के लिए मरीज़ को जिंदा बचा ले पाना संभव नहीं होता। इस बीमारी में मरीज़ पानी से डरता है और कुत्ते की तरह भौंकता-भौंकता इस दुनिया से विदा हो जाता है।

आवारा पशुओं को पकड़ना और उन्हें नियंत्रण में रखना नगर निगम का काम है। पर नगर निगम के लोग़ों को अपने धंधों से फुर्सत मिले तब वे इस ओर ध्यान दें। कुत्ते काटते हैँ तोक काटें, लोग़ मरते हैं तो मरें, उनकी बला से। उल्लेखनीय है कि कुत्ता काटता है भी तो ग़रीबों के बच्चों को ही जो सड़कों पर और गलियों में खेलते हैं। किसी अमीरज़ादे को कुत्ता शायद ही काटता है, क्योंकि वे अपने घर की चारदीवारी के अंदर अपने विदेशी कुत्तों के साथ खेलते हैं और बाहर जाना होता है तो कार में बैठ कर निकलते हैं। इन्हें कुत्ते क्यों काटेंगे? अगर कुत्ता किसी ग़रीब आदमी के बच्चे को काट ले तो महीने भर की दिहाड़ी इलाज में ही खर्च हो जाती है। मज़दूरों के पास आमदनी का कोई अन्य साधन न होने के कारण कर्ज लेकर काम चलाना पड़ता है जिसका सूद लगातार बढ़ता ही जाता है।

नगर निगम से लोग़ करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि वे आवारा पशुओं से शहर को मुक्ति दिलायें, अन्यथा अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे कोई दूसरा रास्ता अख़्तियार करने के बारे में भी सोच सकते हैं।

सूचना के अधिकार के तहत सवाल पूछने पर नगर निगम ने बताया था कि वह समय-समय पर आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाता है। आवारा पशुओं के अंतर्गत गायें और सांड भी आ जाते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निगम में जानवरों को पकड़ने वाली गाड़ियां भी मंगा ली गई हैं, पर उनका उपयोग किस कार्य के लिये किया जा रहा है, इसका पता आज तक नहीं चला। नगर निगम को यह भी पता नहीं कि शहर में कितने आवारा पशु मौजूद हैं। अब कुत्तों के अलावा बंदरों का उत्पात भी बढ़ता चला जा रहा है। ये वो बंदर हैं जिन्हें दिल्ली से पकड़ कर फ़रीदाबाद की सीमा में छोड़ दिया गया। उल्लेखनीय है कि एक बंदर के पकड़े जाने पर सैंकड़ों रुपये खर्च किये गये थे। ऐसे खर्च का क्या फ़ायदा कि उन्हें एक जगह से पकड़ कर चंद किलोमीटर की दूरी पर छोड़ दिया जाये। यह तो ठेका देने के पहले ही स्पष्ट कर देना चाहिए था कि पकड़े गये बंदर कहां छोड़े जायेंगे। यह नहीं भूलना चाहिए कि बंदर के काटने का इलाज भी वही होता है जो कुत्ता काटने का। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि बंदर किसी बच्चे को पकड़ लेगा तो ज़्यादा ही घायल कर देगा।

अभी कुत्तों का मेटिंग सीज़न चल रहा है। इस दौरान सुध-बुध खोकर कुत्तियों के पीछे दौड़ लगाते हैं और कुत्तियों पर अधिकार जमाने के लिए आपस में उनमें झगड़े भी होते हैं। उनके इस झगड़े के दौरान अगर कोई बच्चा अथवा बड़ा व्यक्ति पड़ गया तो उसकी खैर नहीं है। उसे ये लहुलुहान किये बिना ये नहीं मानते।

कुत्तों को छोड़ दें तो बीच सड़क पर सांड और गायें भी पड़ी जुगाली करती रहती है। इससे वाहनों के आने-जाने में भारी परेशानी होती है। ये भारी जानवर जल्दी से हट कर एक किनारे भी नहीं हो पाते। परिणामस्वरूप कई बार दुर्घटनायें हो चुकी हैं। यह ठीक है कि नगर निगम की व्यस्तता ज्यादा है। उसे ऐसे कामों में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है जो पशुओं नहीं, मनुष्यों से संबंधित हैं और जिनमें अतिरिक्त कमाई का जुगाड़ भी होता है। पर सिर्फ़ इस वजह से पशुओं की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। नगर निगम से फरीदाबाद के लोग़ करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि वे आवारा पशुओं से शहर को मुक्ति दिलायें, अन्यथा अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे कोई दूसरा रास्ता अख़्तियार करने के बारे में भी सोच सकते हैं।

सीवर में मरते मज़दूर

फरीदाबाद (म.मो.) अक्सर ही ऐसी ख़बरें आती हैं कि सीवर की सफ़ाई के लिए उसमें उतरे मज़दूरों की दम घुटने से मौत हो गई। एकाध बार ऐसी दुर्घटना हो जाये तो समझ में भी आता है कि लापरवाही अथवा ध्यान न देने से ऐसा हो गया। पर जब बार-बार इस तरह की ख़बरें आयें तो सोचने को मज़बूर होना पड़ता है कि आख़िर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए दोषी कौन है?

सीवर लाइन की सफ़ाई करवाना नगर निगम का काम है। वैसे, वह अपनी इस ज़िम्मेवारी के प्रति सजग नहीं है और जब सीवर जाम हो जाते हैं तो लोग़ भी सफ़ाई कर्मियों को पैसे देकर सीवर की सफ़ाई करवा लेते हैं। लेकिन सीवर की सफ़ाई करवाना सिर्फ़ और सिर्फ़ नगर निगम का काम है।

एक खास बात यह भी दिखाई पड़ती है कि सफ़ाई करने के लिए सीवर में उतरे कर्मी की जब दम घुटने अथवा विषैली गैस के प्रभाव में मौत हो जाती है तो इसे कोई मुद्दा नहीं बनाता। मज़दूर के परिवार वाले रो-पीट कर चले जाते हैं। अगर सफ़ाईकर्मी नगर निगम का हुआ तो उसे कुछ मुआवज़ा राशि मिल जाती है, लेकिन जो सामान्य सफ़ाईकर्मी होता है, उसे मुआवज़ा कौन देगा? यह एक बड़ी ही विचित्र स्थिति है। इस पर नगर निगम ने जो ठंडा, संवेदनहीन रुख अपनाया हुआ है, इससे पता चलता है कि उसका चरित्र किस हद तक जनविरोधी हो चुका है। 22 सिंतबर को सेक्टर-24 में काले और जॉनी नामक दो मज़दूर एक फ़ैक्ट्री के सीवर की सफ़ाई करने के लिए सीवर के अंदर गये। पहले सीवर में काले नाम का मज़दूर उतरा। वहां दम घुटने से उसकी हालत खराब होने लगी तो उसे बचाने के लिए जॉनी भी सीवर में उतरा। जहरीली गैस के कारण उसका दम भी घुटने लगा तो लोग़ों ने फ़ोन कर नगर निगम और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद नगर निगम से बचाव दल आया और दोनों को सीवर से निकाल कर बीके अस्पताल पहुंचाया। वहां काले की मौत हो गई और जॉनी अपनी ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है।

अगर शहर में इक्का-दुक्का ऐसी घटनायें होतीं तो किसी का ध्यान नहीं जाता। पर ऐसी घटनायें बेशुमार हो रही हैं। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ़ यहीं सीवर की सफ़ाई के लिए सफ़ाई कर्मी उनमें उतरते हैं।

हर जगह सीवरों की सफ़ाई होती है। पर इतने बड़े पैमाने पर सफ़ाईकमयों की मौत के बारे में कहीं नहीं सुना गया है। सीवर में उतरने के भी कुछ नियम और कायदे हैं। सीवर सफ़ाईकर्मी बाकायदा हेलमेट लगाये होते हैं, साथ ही सीवर में उतरने से पहले ऑक्सीजन मास्क उन्हें पहनना होता है ताकि विषैली गैस से उनकी रक्षा हो सके। पर यहां ऐसा कुछ नहीं है। बहुत हुआ तो सफ़ाईकर्मी पव्वा-अद्धा चढ़ा कर नशें की हालत में सीवर में जोश में उतर जाते हैं और फ़िर अंदर से निकलती है उनकी लाश। इसके लिए और कोई नहीं सिर्फ़ नगर निगम जिम्मेदार है। इस तरह के मामलों में नगर निगम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।

हरियाणा विधानसभा चुनाव

समीकरण हैं कांग्रेस के पक्ष में

हरियाणा विधानसभा चुनाव 13 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। एक तरफ सत्ताधारी कांग्रेस जहां अपनी जीत को ले कर पूर्णत: आश्वस्त है, वहीं दूसरे दल गठबंधनों को लेकर असमंजस की स्थिति में थे। कांग्रेस के अलावा चुनाव मैदान में इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो), बहुजन समाज पार्टी (बसपा), हरियाणा जनहित कांग्रेस (हजकां) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हैं। ये सभी दल अपने आप को इस स्थिति में नहीं पा रहे हैं कि स्वतंत्र रूप से चुनाव जीतने को लेकर आश्वस्त हो सकें। इसलिए इनमें गठबंधन बनाने की बात काफ़ी पहले से चली आ रही थी। भाजपा, कांग्रेस और एक हद तक बसपा को छोड़ कर शेष बचे दोनों दलों की कोई राष्ट्रीय पहचान नहीं है। ये विशुद्ध रूप से राज्य स्तरीय पार्टियां हैं। राज्य में भी इनका जनाधार कितना है, इसका पता लोकसभा चुनाव में चल चुका है। इसलिए इनमें भाजपा और बसपा के साथ गठबंधन बनाने के लिए काफ़ी प्रयास हुए। इधर, भाजपा और बसपा का भी राज्य में कोई खास जनाधार नहीं है। भाजपा और बसपा का यह हाल है कि उनके राज्य अध्यक्षों को कोई अच्छी तरह जानने वाला नहीं। हजकां के कुलदीप की पहचान महज़ भजनलाल के पुत्र के रूप में है। उनका स्वतंत्र कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। रह गये इनेलो के ओम प्रकाश चौटाला तो ये 'बदनाम होंगे तो क्या नाम न होगा' की तर्ज पर राष्ट्रीय राजनीति में जाने जाते हैं, लेकिन राज्य में इनका क्या जनाधार रह गया है, यह लोकसभा चुनाव में अच्छी तरह पता चल गया। इन्होंने वामपंथियों द्वारा कांगेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार से समर्थन वापस लेने के पहले मुलायम सिंह द्वारा बनाये जा रहे तीसरा मोर्चा में भागीदारी की थी, पर जब वामपंथियों ने संप्रग सरकार से समर्थन वापस ले लिया तो मुलायम सिंह ने सरकार को बचाने का फ़ैसला किया और तीसरा मोर्चा बनने के पहले ही भराभरा कर गिर गया। चौटाला फ़िर अकेले हो गये। इन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन की बात चलाई, पर विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाने के कारण गठबंधन सिरे नहीं चढ़ पाया। अब ये अकेले अपने दम पर चुनाव के मैदान-ए-जंग में उतर चुके हैं।

बहरहाल, जहां तक गठबंधन का प्रश्न है, हजकां के साथ बसपा के गठबंधन की संभावना समाप्त हो जाने के बाद कुलदीप ने कोशिश की थी कि उसका भाजपा के साथ गठबंधन कायम हो जाये। इस गठबंधन के लिए दोनों दलों की ओर से काफ़ी प्रयास किये गये, पर सीटों के बंटवारे के सवाल को लेकर विवाद खत्म न हो पाने के कारण इस बात की संभावना समाप्त हो गई है। वास्तव में, अब भाजपा में अंतर्कलह अपने चरम पर है। राजनीतिक सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर कहा जा सकता है कि गठबंधन की राजनीति विधानसभा चुनाव में नहीं चल पायेगी। इनेलो, बसपा, भाजपा और हजकां अपने-अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरेंगी। इसका फायदा कांग्रेस को मिलना तय है।

मुख्यमंत्री हुड्डा ने समय से पूर्व चुनाव इसलिए करवाना चाहा ताकि लोकसभा में कांग्रेस की जीत को राज्य में भुनाया जा सके। हरियाणा की राजनीति में जाटवाद और जातिवाद का प्राबल्य है। हरियाणा में दलितों के बाद जाटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। जाटों के वोट अगर कांग्रेस और इनेलो के बीच बंटते हैं तो भी बसपा की मौजूदगी के बावजूद दलितों के वोट कांग्रेस को भी मिलेंगे। दलितों के वोटों पर इनेलो कब्ज़ा कर पाये, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। जहां तक चुनाव में जीत का सवाल है, अगर कोई चमत्कार न हो तो कांग्रेस ही अगली सरकार बनायेगी। इनेलो, भाजपा, हजकां और बसपा को नाममात्र की सीटों से संतुष्ट होना पड़ेगा।

जहां तक मुद्दों की बात है, अभी संपन्न हुए लोकसभा चुनाव की भांति ही हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी मुद्दों का अकाल है। किसी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसीलिए लगभग सभी पार्टियां बड़ी-बड़ी घोषणायें करने में लगी हुई हैं। पर इस मामले में भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत नज़र आती है। मुख्यमंत्री हुड्डा ने घोषणा-वीर के रूप में अपनी छवि बनाई है। इन्होंने हरियाणा नंबर-वन का नारा उछाला है। लेकिन हरियाणा कितना नंबर-वन है, इस हकीकत को आम जनता अच्छी तरह समझ रही है। राज्य में पानी-बिजली का अकाल है। पूंजीपतियों को देने के लिए किसानों से ज़मीन छीनी गई। इसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सोचने की जरूरत नहीं समझी गई। बिजली की कमी और मंदी का असर उद्योगों पर साफ़ नज़र आने लगा है। बड़े शहरों और कस्बों में लोग़ों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। हरियाणा में जो बिजली उपलब्ध है, वह भी अन्य राज्यों की अपेक्षा काफ़ी महंगी है। आम जनता के लिए शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था बड़ी ही बदहाल है। सिर्फ़ मुट्ठी भर अमीरों के लिए शिक्षा और चिकित्सा की बड़ी-बड़ी दुकानें खुली हुई हैं।

मुख्यमंत्री हुड्डा ने समय से पूर्व चुनाव इसलिए करवाना चाहा ताकि लोकसभा में कांग्रेस की जीत को राज्य में भुनाया जा सके। हरियाणा की राजनीति में जाटवाद और जातिवाद का प्राबल्य है। हरियाणा में दलितों के बाद जाटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। जाटों के वोट अगर कांग्रेस और इनेलो के बीच बंटते हैं तो भी बसपा की मौजूदगी के बावजूद दलितों के वोट कांग्रेस को भी मिलेंगे। दलितों के वोटों पर इनेलो कब्ज़ा कर पाये, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। जहां तक चुनाव में जीत का सवाल है, अगर कोई चमत्कार न हो तो कांग्रेस ही अगली सरकार बनायेगी। इनेलो, भाजपा, हजकां और बसपा को नाममात्र की सीटों से संतुष्ट होना पड़ेगा।

- प्रतिनिधि